

मोदी सरकार की विदेश नीति सफल रही या असफल?

यह मुद्दा रहेगा, संसद के आगामी सत्र में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जून। मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलताओं को लेकर बढ़ती आलोचना अब सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि पहलुगाम आतंकी हमले और इसके बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने से इनकार किए जाने के बाद विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर घोर लापरवाही और कई कूटनीतिक मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से कोई ठोस परिणाम न निकलने को लेकर विपक्ष ने सरकार की कड़ी आलोचना की है और 33 देशों का दौरा करने वाले बहुप्रचारित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद में कथित भूमिका को उजागर कर वैश्विक समर्थन जुटाना था, वह भी इस्लामाबाद को अलग-थलग करने की दिशा में कोई ठोस आश्वासन या अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में असफल रहा है। कूटनीतिक शर्मिंदगी को और गहरा करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की

- विपक्ष का कहना है, बहुप्रचारित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जो 33 राज्यों में भेजा गया, उसे, आतंकवाद के प्रश्न पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयास में खास सफलता नहीं मिली और न ही कोई ठोस आश्वासन मिला।
- दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन्स की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी कमेटी में पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन के रूप में मनोनीत होना, भारत के उन प्रयासों के लिए भारी धक्का है, जो भारत काफी समय से कर रहा है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी नेटवर्क्स को प्रश्रय देने की सच्चाई को उजागर करने के लिए।
- साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा करने से कि उनकी सक्रिय भूमिका के कारण भारत व पाक के बीच “सीज़फायर” हुई, से भारत की विदेश नीति की “स्वतंत्रता” पर आघात हुआ है और अब तो ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि उनको “सीज़फायर” लागू करने के प्रयास में रूस का भी समर्थन प्राप्त था।
- सरकार का इस बारे में यह कहना है कि दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति सही दिशा में अग्रसर है तथा छोटे-मोटे घटनाक्रमों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

आतंकवाद-रोधी समिति में पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाना, आतंकी नेटवर्क को पनाह एवं संरक्षण देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने से सम्बंधित भारत के लम्बे समय से चल रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह घटनाक्रम भारत की वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लम्बे समय से चली आ रही मुहिम की साख को कमजोर करता है। स्थिति को और पेचीदा बनाते हुए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह नया दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच “तनावपूर्ण गतिरोध” के दौरान युद्धिवराम कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इस प्रक्रिया में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सहयोग किया था। इस दावे ने भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की इन टिप्पणियों ने भारत की बड़ी शक्तियों पर बढ़ती निर्भरता और सुरक्षा मामलों पर सीमित होती जा रही कूटनीतिक स्वतंत्रता को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नयी दिल्ली, 06 जून। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025, तीन अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की शुरुवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने एनबीई की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की अनुमति दे दी। परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होगी।

अदालत ने इस संस्था की दलीलों विस्तार पूर्वक सुनने के बाद परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पहले 30 मई को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने अदिति और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनबीई को 15 जून को पूर्व निर्धारित दो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने ट्रंप-मस्क की सार्वजनिक छींटाकशी व झगड़े पर कटाक्ष किया

कांग्रेस ने कहा, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, यह ट्रंप व मस्क को अडानी व मोदी की “दोस्ती” से सीखना चाहिए

- कांग्रेस ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि मोदी-अडानी “दोस्ती” पिछले तेईस सालों से चल रही है और कोई बदमजगी की बात न सुनी और न देखी।
- जैसा कि विदित ही है, मस्क ने ट्रम्प के व्यक्तिगत आचरण को भी नहीं बक्शा और कहा कि एफ्टीन फाइल्स इसलिए सार्वजनिक नहीं हो रहीं, क्योंकि उनमें राष्ट्रपति ट्रंप का नाम है। एफ्टीन एक अंतर्राष्ट्रीय दलाल थे, जिन पर हाई-सोसायटी की पार्टियों में युवतियों व बच्चियों को स्पलाई करने का आरोप है।

आलोचना की। इस बिल को हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित किया है। इसके बाद मस्क ने एक्स पर धमाका करते हुए लिखा: “अब असली बम गिराने का वक़्त है: असली ट्रंप तो एफ्टीन फाइल्स में हैं। यही असली वजह है कि उन फाइल्स को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुडलक डोज़ेटी।” हालांकि मस्क ने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया, फिर भी यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया।

आलोचकों ने तुरंत मस्क के थिसलेन मैक्सवेल, जो जेफरी एस्पटीन की करीबी सहयोगी थीं, के साथ संबंधों की याद दिलाई, जिससे यह मामला और गर्मा गया। भारत में, कांग्रेस ने इस अवसर का उपयोग मोदी और अडानी के कथित घनिष्ठ रिश्तों को फिर से उजागर करने के लिए किया। वर्षों से यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर अडानी समूह की वैश्विक व्यापारिक विस्तार योजनाओं के साथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिक्स देशों ने भारत की आतंक के खिलाफ “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति पर सहमति दी

नयी दिल्ली। ब्राजीलिया, 06 जून। ब्रिक्स देशों ने पहलुगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सहमति जताई है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भारत सहित, 10

सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष अघ्यक्ष ओम बिड़ला सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिक्स संसदीय फोरम का 12वां सम्मेलन भारत में होगा, इसलिए सम्मेलन के अंतिम दिन बिरला को अध्यक्षता सौंपी गई है। ब्रिक्स संसदीय

सम्मेलन में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिख, इथियोपिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए साझा घोषणापत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वक्फ संबंधित उम्मीद पोर्टल लॉन्च

नयी दिल्ली, 06 जून। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने केंद्रीय पोर्टल ‘उम्मीद’ का शुभारंभ करने के बाद शुरुवार को कहा कि यह वक्फ संपत्ति प्रबंधन तथा प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। रिजिजू ने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी। यह पोर्टल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

भगवान सिंह रोलसाबसर का निधन

जयपुर, 6 जून। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाबसर का गुरुवार देर रात जयपुर में निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके

- क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दुःख व्यक्त किया।

निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे सहित, कई नेताओं ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोलसाहबसर के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या “इमरजेंसी” पर बहस करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत होगा?

कांग्रेस इस अफवाह से विचलित है तथा संभावित सत्र को पहलुगाम व ऑपरेशन सिंदूर की कमियों से ध्यान हटाने की साजिश बताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जून। फिलहाल भारत सरकार की ओर से 25 जून 2025 को 1975 की इमरजेंसी पर चर्चा के लिए किसी विशेष संसद सत्र को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बजाय, सरकार ने 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने की घोषणा की है, ताकि विशेष सत्र की मांगों को रोका जा सके। तथापि, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सरकार 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर

- हालांकि, सरकार की ओर से ऐसे सत्र बुलाने या न बुलाने के बारे में अधिकृत रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, पर, इंडिया गठबंधन, जिसे 16 राजनीतिक दल, जैसे, कांग्रेस, सपा, डीएमके तथा तृणमूल कांग्रेस आदि पार्टियां शामिल हैं, ने प्र.मंत्री से आग्रह किया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर व देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण हो सके।

एक विशेष सत्र आयोजित करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस संभावित कदम की आलोचना करते हुए इसे हाल की

पहलुगाम आतंकी घटना और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन ‘सिंदूर’ जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब आर.टी.जी.एस. से पैसा ट्रांसफर लगभग सभी करते हैं

पर, इस रियल टाइम सैटलमेंट व्यवस्था (आर.टी.जी.एस.) की जितनी उपयोगिता आज है, उतनी ही रोचक उसकी ऐतिहासिक कहानी भी है

-अंजन रॉय-
नई दिल्ली, 6 जून। अगर आपने अपने बैंक खाते से किसी अन्य खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो संभवतः आपने आर.टी.जी.एस. प्रणाली का उपयोग किया होगा। यह तो ज्ञात है, लेकिन आर.टी.जी.एस. प्लेटफॉर्म और उसके विकास के बारे में बहुत कम जानकारी है। रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) प्रणाली को मूल रूप से विभिन्न देशों के बैंकों के बीच बैंक खातों के सैटलमेंट के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद, विजयी देशों ने जर्मनी से “वॉर डैमेजेज” (युद्ध में हुई भारी क्षति) की भरपाई की मांग की।
- यह रकम बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट (बी.आई.एस.) को ट्रांसफर होती थी, उसके बाद बी.आई.एस. विजयी शक्तियों के दावों को “सैटल” करता था। पर, 1932 के वरसाय एग्रीमेंट के बाद, यह महसूस किया गया कि जर्मनी इन दावों की रकम देने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतः, बी.आई.एस. का रोल खत्म सा मान लिया गया था।

(बी.आई.एस.) द्वारा विकसित किया गया था। बाद में इसका उपयोग तेजी से

बढ़ा। अब, बी.आई.एस., बैंकिंग से जुड़े खतरों से विवेकपूर्ण तरीके से निपटने के नियम बनाने वाली प्रमुख संस्था है। बेसल एक, बेसल दो, और बेसल तीन - ये बैंकों के लिए, उनके जोखिम के संदर्भ कैपिटल रिकवियरमेंट (पूंजी की आवश्यकता) के तीन लैवल हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि बैंक अपने व्यापार के स्तर और आकार के अनुसार कितनी स्वयं की पूंजी बनाए रखें। इन्हें बेसल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (पूंजी पर्याप्तता अनुपात) कहा जाता है। इस प्रकार, बी.आई.एस. (बैंक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले दो डॉक्टर्स सहित मेडिकल छात्र गिरफ्तार

नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले

जयपुर। चौमूं थाना पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले तीन डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इनमें डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले दो डॉक्टर भी शामिल है और अन्य आरोपित मेडिकल छात्र है। जिसने परीक्षा पास करने के लिए साठ लाख

- डॉक्टर सुभाष के जरिए 60 लाख रुपए में परीक्षा पास करवाने का सौदा किया**

रुपए में सौदा किया था। पुलिस फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपी डॉक्टर्स से पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि चौमूं थाना पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सुभाष सैनी (3३) निवासी जैतपुरा चौमूं, सचिन गोरा (22) और अजीत गोरा (30) निवासी लक्ष्मी विहार, कचौलिया चौमूं को गिरफ्तार किया है।आरोपित सचिन गोरा वर्तमान में एमबीबीएस फाइनल ईयर एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। जांच में सामने आया कि नीट परीक्षा में सचिन गोरा के जगह अजीत



चौमूं पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया ।

गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा में 667 अंक हासिल किए थे। इसके आधार पर सचिन गोरा का एमबीबीएस के लिए जोधपुर एम्स

में दाखिला हो गया था। सचिन गोरा ने कभी नीट परीक्षा दी ही नहीं।

एसीपी (चौमूं) अशोक चौहान ने बताया कि आरोपित सचिन गोरा ने साल-2020 में आयोजित नीट यूजी परीक्षा को

पास करने के लिए डॉक्टर सुभाष सैनी से सम्पर्क किया। उस समय सुभाष सैनी आयु विज्ञान की डिग्री लेकर वर्तमान में कामन हेल्थ ऑफिसर के पद पर घाटवा में पदस्थापित है। डॉक्टर सुभाष सैनी के जरिए 60 लाख रुपए में परीक्षा पास करवाने का सौदा किया गया। सचिन को जगह परमिशन लेटर पर अजीत की फोटो लगाकर पास कराया गया। पूछताछ में सामने आया है कि साल-2013 में आरोपित सुभाष सैनी ने नीट पीजी में पास करवाने के एवज में 65 लाख रुपए लिए थे। करणी विहार थाना पुलिस ने साल-2013 में प्रकरण में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि चौमूं निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने मामला दर्ज कवाया था। जहां जांच के दौरान पिछले 15 दिनों में कार्रवाई में एनटीए और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया गया था और परमिशन लेटर में भी सचिन की जगह अजीत के फोटो लगाकर एजाम देना सामने आया था। इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर और एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी आवश्यक रिकॉर्ड मांगा गया था। वहीं मामले के खुलासे में भरतपुर और जोधपुर पुलिस ने भी मदद की। जब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया।

थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जयपुर। चाकसू थाना इलाके में नेशनल हाईवे-52 पर तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर 200 मीटर दूर गिरा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

बेकाबू होकर थार ड्रिवाइडर पर चढ़ गई। थार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा टिगरिया चौराहे पर हुआ था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें थार की टक्कर से बाइक सवार उछलता नजर आ रहा है।

थानाधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि बाइक सवार युवक चाकसू से मंडालिया रोड की तरफ जाने के लिए हाईवे क्रॉस कर रहा था। इस दौरान जयपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार हट जाकर गिरा, जबकि थार बेकाबू होकर ड्रिवाइडर पर चढ़ गई।

हादसे के बाद लोगों ने चाकसू पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक सवार को एंबुलेंस से उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शव को मॉर्च्युरी में रखवा दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश कर रही है।

जयपुर-अजमेर हाईवे पर सीएनजी गैस लीक से मची अफरा तफरी

बड़ा हादसा होने से टला

- भांक्रोटा थाना इलाके में टोरेंट कंपनी के करियर ट्रक के मेन पाइप के टूटने से सीएनजी गैस लीक हो गई। सीएनजी गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया**

को सूचना देने के साथ ही हाईवे पर मौजूद अन्य ट्रक चालको की मदद से दोनों ओर का ट्रैफिक रोक गया। पुलिस सहित मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ट्रक में कई सारे सीएनजी गैस सिलेंडर भरे हुए मिले।

ट्रक ले जाते समय रास्ते में मेन पाइप टूटने से सीएनजी गैस लीकेज के चलते रिसाव हो रहा था। जहां चालक ने सूझबूझ के चलते कपड़े से गैस के लीकेज को कम करने का प्रयास किया। पुलिस व फायर ब्रिगेड कर्मियों ने हाईवे से करियर ट्रक को बाईपास स्थित सुनसन जगह ले गए। वहां लीकेज पाइप लाइन को मशकत कर गैस रिसाव को रोका। इसके बाद पुलिस-प्रशासन सहित मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली गई। रिसाव से निकली सीएनजी गैस के हवा में आसनी से घुल जाने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया।

जहां सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा एक ट्रक भांक्रोटा की ओर जा रहा था। इसी दौरान कार शोरूम के सामने से जाते समय सिलेंडर का वाल लीक हो गया। इससे सीएनजी गैस का रिसाव होत लगा। गैस रिसाव का पता चलने पर चालक ने तुरंत ट्रक को रोड किनारे रोक कर मासुले की जानकारी पुलिस को दी। इधर पुलिस

फर्जी पीएम किसान ऐप से साइबर ठगी का नया जाल

जयपुर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया साइबर जाल फैलाया जा रहा है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर किसान सम्मान निधि योजना की मोबाइल एप्लीकेशन

होने का दावा करने वाला एक फर्जी लिंक या एपीके फाइल शेयर कर लोगों को फांस रहे हैं। राजस्थान पुलिस को साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को इस संबंध में सतर्क करते हुए एडवाइजरी जारी की है।

एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार पीएम किसान रजिस्ट्रेशन एवं पीएम किसान योजना की फर्जी एपीके फाइल व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य माध्यमों से शेयर की जा रही है।

जागृति, संवाद एवं डॉन विषयों पर कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जयपुर, 06 जून। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, जयपुर महानगर-प्रथम के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा चलाई जा

रही जागृति, डॉन व आशा योजनाओं के संबंध में कार्यशाला एवं मासिक बैठक का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पवन कुमार जीनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, दीपेन्द्र माथुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर महानगर-प्रथम, कुंतल विस्नोई एडोएल 03, वृजमोहन मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, बबीता राजावत सहायक निदेशक शिक्षा विभाग, श्रीमान बी.पी चंदेल संयुक्त निदेशक समाज कल्याण विभाग, अनिता मुवाल सहायक निदेशक बाल अधिकारिता

विभाग, इंदिरा शर्मा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पैनल अधिकता, पीएलवी व अन्य सदस्यगण उपस्थित रहें। इस दौरान पवन जीनवाल द्वारा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में चलाई जा रही जागृति (जस्टिस अवेयरनेस फॉर ग्रासरूट

इनफार्मेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन्सिप्टिव), डॉन (ड्रग एवैयरनेस एण्ड वेलनेस नेवेगेशन), आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्यवाही) मानक संचालन प्रक्रिया-बाल विवाह से मुक्ति की ओर अग्रसर, 2025 आदि के विषय में जानकारी दी।

पीजी कोर्स के बाद डॉक्टर्स सेवाएं नहीं दे तो दस लाख रुपए करें अदा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अन्य मेडिकल कॉलेजों से पीजी कोर्स करने के बाद सीनियर रेजिडेंट शिप नहीं करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को उनके मूल दस्तावेज लौटाने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार को यह

अंडरटेकिंग दें कि यदि वे एसआरशिप ज्वानन नहीं करेंगे तो दस लाख रुपए की बॉन्ड राशि का भुगतान करेंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. सैयद शाबाज सहित करीब दो सौ से अधिक याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को पुनर्विचार अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मुद्दा खंडपीठ में लंबित चल रहा है। ऐसे में एकलपीठ इसमें आदेश पारित नहीं कर सकता।

याचिका में अधिवक्ता कुशाग्र शर्मा और पूर्व माथुर ने बताया कि पीजी कोर्स में प्रवेश के समय याचिकाकर्ताओं से दस लाख रुपए का बॉन्ड लिया जाता है कि यदि वे कोर्स के बाद दो साल तक राज्य सरकार को सेवा नहीं दें तो इस राशि का भुगतान राज्य सरकार के पक्ष में किया जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं से उनके मूल दस्तावेज भी जमा करा लिए जाते हैं। याचिका में कहा गया कि मूल दस्तावेज रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं नेशनल मेडिकल कमिशन ने भी इस दस्तावेज रोकने की कोई व्यवस्था नहीं दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट की एकलपीठ पूर्व में यह दस्तावेज जारी करने के निर्देश दे चुका है।

राहगीरों का अपहरण कर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को धर-दबोचा

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय राहगीरों का अपहरण कर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है।

- पूछताछ में करधनी,मुरलीपुरा, करणी विहार सहित अन्य थाना इलाके में आधा दर्जन से अधिक लूटपाट की वारदातों को अंजाम देना कबूला है।**

को धर-दबोचा है। साथ ही पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान रेंटल कार का उपयोग करते हैं। पुलिस पूछताछ में अब तक आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करधनी

‘शाहपुरा पंचायत समिति की प्रधान नहीं करें मितिंग,ना ही जारी करे कोई आदेश’

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहपुरा पंचायत समिति की प्रधान से जुड़े मामले में कहा है कि वह निर्वाचित प्रधान नहीं है और उन्हें राज्य सरकार ने इस पद का कार्यभार सौंपा है। ऐसे में वे कोई भी बैठक आहूत ना करें। वहीं अदालत ने किसी भी प्रकार का निर्णय भी नहीं लेने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यदि नियम अनुमति देते हैं तो राज्य सरकार प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित कर सकती है। जस्टिस अशोक कुमार जैन और अवकाशकालीन न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश मंजू देवी शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शाहपुरा पंचायत समिति की वार्ड संख्या 15 से सदस्य निर्वाचित हुई थी। वहीं बाद में सभी वार्ड सदस्यों ने उसे प्रधान के रूप में चुना था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने शाहपुरा नगर परिषद के क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें याचिकाकर्ता के वार्ड को भी शामिल कर लिया। वहीं बाद में उसे यह कहते हुए वार्ड सदस्य पद से हटा दिया

- अदालत ने कहा है कि यदि नियम अनुमति देते हैं तो राज्य सरकार प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित करा सकते हैं**

कि अब वार्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इसके बाद गत 15 मई को याचिकाकर्ता से प्रधान पद का कार्यभार लेकर उसे पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 की सदस्य पिस्ता देवी को सौंप दिया। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि उसका वार्ड सदस्य के रूप में अलग चुनाव हुआ था और बाद में प्रधान पद के लिए अलग से मतदान हुआ था। ऐसे में वार्ड का अस्तित्व समाप्त होने के आधार पर उसे प्रधान पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए दूसरे वार्ड सदस्य को सौंपा गया कार्यभार का आदेश रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कार्यवाहक प्रधान को बैठक आहूत करने और किसी भी तरह का निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।

सद्भावना के सिपाही संगठन की आम सभा आयोजित

जयपुर । सद्भावना के सिपाही संगठन की जयपुर जिला इकाई की आम सभा आयोजित कैलाश शर्मा (गुरुजी) अध्यक्ष और अजय सक्सेना कार्यकारी अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित सद्भावना और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित सद्भावना के सिपाही संगठन की जयपुर जिला इकाई की आम सभा आज सादगी और उत्साह के साथ आयोजित की गई। संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख पूर्व राज्यमंत्री राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में संचालित इस संगठन की बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। आम सभा में सर्वसम्मति से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश शर्मा (गुरुजी) को जिला अध्यक्ष तथा एडवोकेट अजय सक्सेना को कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने संगठन के संस्थापक स्व. सुनील दत्त की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। पूर्व राज्यमंत्री राजीव अरोड़ा ने नव निर्वाचित अध्यक्ष कैलाश शर्मा (गुरुजी) एवं कार्यकारी अध्यक्ष अजय सक्सेना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, सेवा और सकारात्मक बदलाव लाना है।

डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक

जयपुर। विगत तीन वर्षों से जयपुर में डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता ने अपने म्यूजिकल मैचों की अनूठी संकल्पना के चलते अब तक बहुत सराहना बटोरी है।

डी एम पी एल के संयोजक डॉ सदीप निज़ाम ने बताया कि सफलता के इसी क्रम को जारी रखते हुए इस वर्ष भी 25 से 27 जुलाई तक के चौथे संस्करण के टीम इवेंट का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। लीग चेयरमैन डॉ संजीव गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग डॉक्टर्स द्वारा डॉक्टर्स के लिए आयोजित होने वाली अनोखी गायन प्रतियोगिता है, जहाँ दिन में चिकित्सकीय कौशल दिखाने वाले करीब 200 डॉक्टरों को अपने सुरों का कौशल दिखाना है।

लीग के चीफ कोऑर्डिनेटर डा. हरीश भादुराज ने बताया कि प्रतियोगिता की रूपरेखा तय हो चुकी है, लीग में टीम इवेंट्स के अलावा व्यक्तिगत प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी जिसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में एकल व युगल गायन प्रतियोगिता का ऑडिशन 6 जुलाई को किया जाएगा।

प्रतियोगिता के चीफ कॉर्डिनेटर डॉ हर्षुल टाक व डॉ रवींद्र सिसोदिया ने

कृषक नवीन तकनीकी को अपनाकर वैज्ञानिक तरीके से करे खेती : राजन विशाल

जयपुर । शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शुक्रवार को जयपुर के बसेडी, बस्सी झाड़डा, गुढा कुमावतान क्षेत्रों का भ्रमण किया। उनके द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल कलस्टर बस्सी झाड़डा में कृषक अशोक निठारवाल के खेत पर स्थापित ग्रीन हाउस, फार्म पोण्ड ,ड्रिप संयंत्र तथा अन्य

- शासन सचिव ने हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल कलस्टर बस्सी झाड़डा क्षेत्र के चयनित कृषकों के साथ कृषक गोष्ठी का आयोजन कर किसानों से संवाद किया**

उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया।

शासन सचिव ने हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल कलस्टर बस्सी झाड़डा क्षेत्र के चयनित कृषकों के साथ कृषक गोष्ठी का आयोजन कर किसानों से संवाद किया। कृषकों द्वारा उद्यानिकी



शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने जयपुर के बसेडी, बस्सी झाड़डा, गुढा कुमावतान क्षेत्रों का दौरा किया।

विकास की गतिविधियों का लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा किसानों को ग्रीन हाउस में फसल विविधिकरण के तहत खीरा फसल के अलावा शिमला मिर्च, कटफलोवर (डचरोज), ब्लैकबेरी आदि फसले लेने हेतु प्रेरित किया गया

ताकि किसानों को अधिक आर्थिक लाभ हो। गोष्ठी में किसानों से ग्रीन हाउस के आर्थिक मूल्यंकन पर भी चर्चा की गई।

राजन विशाल ने कृषक भैरूराम थाकण द्वारा गमी में बोये गये खीरं के खेत एवं कटफलोवर (डचरोज) के खेत का भ्रमण किया तथा कटफलोवर (डचरोज)

के विपणन के बारे में किसानों को स्थानीय होटल व्यवसायियों से सम्पर्क कर विपणन किये जाने की सलाह दी। कृषक भैरूराम थाकण, ग्राम बसेडी के खेत पर ही स्थापित पी.एम.कुसुम कम्प्योनेन्ट ‘बी’ के तहत सौर उर्जा पम्प संयंत्र का निरीक्षण किया। शासन सचिव द्वारा सभी किसानों को संरक्षित खेती के तहत उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने हेतु उद्यानिकी की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुये वैज्ञानिक तरीके से खेती किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। किसानों द्वारा डचरोज को लम्बे समय तक संरक्षित रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटड वैन पर अनुदान दिये जाने की मांग की गई। किसानों की मांग पर शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटड वैन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अतः कृषक इस हेतु आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ताकि कृषकों को डचरोज के विपणन में कोई असुविधा न हो। उक्त भ्रमण के दौरान संयुक्त निदेशक उद्यान प्रदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक उद्यान (मु0) दानवीर वामन एवं उप निषेक उपायन दुर्गापुर, जयपुर, हरलाल सिंह बिजारनियां उपस्थित रहे।



जयपुर । राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन के बैंक कर्मचारी नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस व ताक दा जन्म शताब्दी अवसर पर राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन के चेयरमैन आर जी शर्मा, सचिव महेश शर्मा, उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा , एम एस भट्टेजा , रविदीप चतुर्वेदी , रवि कटारिया ,बनवारी लाल, दिलीप जादम पदाधिकारियों के साथ बैंक कर्मियों व महिला विंग संयोजक मेधा मलिक , शिखा बंसल के साथ विभिन्न बैंकों की महिला कर्मियों ने विजयाराजे सिन्धिया पार्क मानसरोवर में अशोक , पीपल व जामुन के पौधें लगाकर वृक्षारोपण किया, साथ ही पक्षियों के लिए दाना– पानी के परिण्डे बांधकर उनमें दाना डाला गया। लगाए गए पेड़ो की देख भाल सम्हाल के लिए पार्क के ताली की सेवाएँ सुनिश्चित की गई। एआईबीईए के स्वर्गीय महासचिव मालेकर चक्रवर्ती की जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष देश के सभी राज्यों में सामाजिक सरोकार के विभिन्न कार्यक्रम होंगे आमेरा ने बताया कि देश के बैंक कर्मियों का सबसे पुराना 20अप्रैल 1946 व सबसे बड़ा एकमात्र संगठन है जो बैंक व बैंकर्मियों की सुरक्षा , समृद्धि व संरक्षण के साथ साथ देश –दुनिया में प्रगृहित आपदा सुनामी से बाढ़ भूकम्प में व कोविड से लेकर युद्ध काल तक में तन –मन-धन से सभी सामाजिक सरोकारों में अपनी राष्टवादी भूमिका पूरी शिदत से निभाता आया है ।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की एसी ट्रेन को रामेश्वरम, मदुरई रवाना किया

उन्होंने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 25-26 का शुभारंभ किया

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 50 हजार वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेनों से 13 तीर्थस्थलों की यात्रा करायेंगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की प्रथम वातानुकूलित “राजस्थान वाहिनी” भारत गौरव पर्यटक ट्रेन” को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनको सुगम एवं सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

जयपुर, 6 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही, योजना के तहत प्रथम वातानुकूलित ‘राजस्थान वाहिनी’ भारत गौरव पर्यटक ट्रेन” को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस एसी ट्रेन से वरिष्ठ नागरिकगण रामेश्वरम एवं मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी सुगम एवं सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके अनुभव और आदर्श

हमें जीवन में सही राह पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जीवन भर समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने वाले वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भाव है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में यह इच्छा रहती है कि वह अपने जीवनकाल में महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की यात्रा करे, वरिष्ठजनों की पावन

धामों के दर्शन करने की इच्छा से प्रेरित होकर यह तीर्थयात्रा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन, ठहरने की सुविधा सहित, सभी आवश्यक सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत, इस साल 50 हजार वरिष्ठजनों को पहली बार एसी ट्रेनों से 13 विभिन्न

तीर्थस्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। इसके पहले लगभग छह हजार श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और उनके परिजन उपस्थित थे।

मोदी सरकार की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर चिंता बढ़ा दी है। शीर्षस्थ कूटनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर होते देख कर चिन्तित एवं आशंकिता दिखाई दे रहे हैं। एक पूर्व भारतीय राजदूत ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “ गहन प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में पाकिस्तान की भूमिका को रोकने में भारत की असफलता यह दर्शा रही है कि विदेश नीति में इरादे और अमल के बीच गहरा खाई है।

पूर्व विदेश मंत्री और मोदी सरकार की विदेश नीति व आर्थिक नीति के प्रघ्नर आलोचक डॉ. के.सी. मेनन ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “भारत की वैश्विक साख पर गंभीर अविश्वास खड़ा हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नतीजों का सामना किए बिना, अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी।”

लेकिन सरकार ने इन आरोपों पर घोर चुप्पी साध ली है। उच्च पदस्थ

‘अपराध गंभीर हो तो एंटीसिपेटरी बेल ना दें’

नई दिल्ली, 6 जून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी पूर्व जमानत बिना सोचे-समझे नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता को पीठ ने यह टिप्पणी बिहार के एक हत्या के मामले में चार आरोपियों को दी गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत रद्द करते हुए की।

पीठ ने 1 मई को दिए गए आदेश में कहा, पटना हाईकोर्ट का आदेश बिना किसी ठोस वजह के दिया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंड मार्क टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। पटना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने के आरोपियों को जमानत दे दी थी।

कोशिश।) जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यह आदेश संक्षिप्त और न्यायिक विश्लेषण से रहित है। ऐसे गंभीर मामलों में इस तरह से स्वचालित रूप से जमानत नहीं दी जा सकती। यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए।मामले में कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता के पिता की उसके सामने ही लोहे की रॉड और डंडों से पीटाई की गई थी, जिससे उसकी उसी दिन मौत हो गई। यह विवाद रास्ते में रुकावट को लेकर हुआ था। एफआईआर में आरोपियों की भूमिका साफ तौर पर बताई गई है।

करोना के एक्टिव केस हुए 5 हजार के पार

नयी दिल्ली, 06 जून। देशभर में कोरोना संक्रमण के 464 सक्रिय मामले बढ़ ने के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या शुक्रवार सुबह 5364 तक पहुंच गयी। पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से चार और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 55 तक पहुंच गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह आठ बजे तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 5364 पहुंच गयी। अभी तक 4724 मरीजों की स्वस्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुटी दे दी गयी है लेकिन इस अवधि के दौरान चार और मरीजों की जान चली गयी।

55 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 1266 मामले सामने आये हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। देश के नौ राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामले सबसे अधिक हैं, जिनमें से केरल, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण के 498 नये सक्रिय मामले सामने आये हैं और 764 मरीजों के स्वस्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुटी दे दी गयी है लेकिन इस अवधि के दौरान चार और मरीजों की जान चली गयी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फॉर इंटरनेशनल सेलमेंट्स) आम जनता के बीच पते ही कम जाना-पहचाना नाम हो, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर देश के पास केंद्रीय बैंक होता है जो प्राइस स्टेबिलिटी और मॉनिटरी सिस्टम की निगरानी करता है, और बी.आई.एस. एक तरह से इन केंद्रीय बैंकों का “बैंकर” है।

बी.आई.एस. ने 17 मई को स्विट्जरलैंड के बाज़ल शहर में अपनी 95वीं वर्षगांठ मनाई, जहाँ इस संस्था द्वारा निर्भाई गई प्रमुख भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया। बी.आई.एस. की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के तुरंत बाद जर्मनी से युद्ध हर्जाने के भुगतान के प्रबंधन के लिए की गई थी।

प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को युद्ध हर्जाने के रूप में भारी भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। ये भुगतान पहले बी.आई.एस.

को दिए जाते थे, जो फिर फ्रांस या ब्रिटेन जैसे विभिन्न देशों के दावे निपटाता था। लेकिन 1932 तक, वर्साय शांति समझौता और उसके हर्जाना भुगतान के प्रावधान अप्रभावी हो गए, क्योंकि जर्मनी इतनी बड़ी रकम चुकाने की स्थिति में नहीं था। जर्मनी में अत्यधिक महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और प्रयासों के बावजूद कोई भी राशि नहीं वसूली जा सकी।

इसलिए बी.आई.एस. की मूल भूमिका अप्रासंगिक हो गई और यह धीरे-धीरे विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच लेनदेन और दावों की निपटाने का मंच बन गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बी.आई.एस. को एक नई भूमिका मिली। यह अमेरिका की मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी रकम के हस्तांतरण का प्लेटफॉर्म बन गया। जून पुनर्निर्माण कार्य धीमा पड़ने लगा, तो बी.आई.एस. एक ऐसा मंच बन गया जहाँ केंद्रीय बैंक अधिकारी मिलकर मौद्रिक स्थिरता और

भगवान सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। देवनानी ने कहा कि उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। उन्होंने जीवनपर्यंत संगठन और समाज की सेवा को अपना धर्म माना।

इसी तरह उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेम चंद बैरवा, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित, कई नेताओं ने शोकसागर के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है।

■ पर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए भारी राशि आई, अमेरिका के मार्शल प्लान के तहत, तब बी.आई.एस. की दुकान फिर चल पड़ी।

■ पर, कालांतर में, बी.आई.एस. को समय की आवश्यकता के अनुसार, अपना स्वरूप व कामकाज बदलना पड़ा और अब आर.टी.जी.एस. के रूप में वह पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय संकटों से गुजरने के अनुभव की उसकी स्मृतियां तथा डेटा बेस उनका सबसे बड़ा “एसैट” (धरोहर) हैं तथा फायनैशियल सिस्टम को संकटों से निपटने के लिए उठाये गये नीतिगत निर्णय व प्रक्रिया, अब भावी संकटों से निपटने में भारी भूमिका निभायेंगे।

नीतियों पर चर्चा करने लगे। केन्द्रीय बैंकों के बीच पॉलिसी पर विचार-विमर्श के लिए बी.आई.एस. प्लेटफॉर्म का मुख्य आधार इसकी मजबूत शोध क्षमताएं और डेटाबेस है। बी.आई.एस. इन केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीतियों पर समन्वय स्थापित

जी-7 की मीटिंग के लिए मोदी को न्यौता

नयी दिल्ली, 06 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 देशों की शिखर बैठक में शामिल होने इस महीने कनाडा जायेंगे। यह बैठक 15 से 17 जून तक अलबर्टा प्रांत के कनानास्किस में होनी है।

मोदी ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने उन्हें फोन कर जी-7 की बैठक का न्यौता दिया। उनकी इस पोस्ट से पिछले कुछ दिनों से भारत के इस बैठक में शामिल होने को लेकर लगायी जा रही अटकलों पर विराम

■ प्र.मंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि कैनडा के प्रधानमंत्री ने फोन करके जी-7 मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया है।

लग गया है। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी का फोन आने पर प्रसन्नता हुई। मैंने उन्हें हाल के चुनावों में मिली विजय के लिए बधाई दी और कनानास्किस में इस महीने होने वाली जी-7 की बैठक में भाग लेने का आमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया।

जी-7 देशों में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन तथा इटली शामिल हैं। मोदी इस शिखर बैठक में विशेष आमंत्रित के तौर पर भाग लेंगे।

‘जम्मू-कश्मीर में बना विकास का माहौल, पहलगाम हमले से नहीं रुकेगा’

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊँचे चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा

पीएम मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर में 46 हजार करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया।

मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के दूरि्रज का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला ईसानियत और कश्मीरियत पर हमला था। यह पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी, जो कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन और आर्थिक विकास को रोकना चाहता था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के वेग को रकने नहीं

- प्रधानमंत्री ने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा ब्रिज है जो केबल स्टैंड तकनीक पर बना है।
- मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में ईसानियत व कश्मीरियत पर हमला किया, वे भारत में दंगे कराना चाहते थे, पर, कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया।

दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में नौजवान आदिल की हत्या का भी उल्लेख किया और कहा कि आदिल वहां मेहनत-मजदूरी करने गया था।

आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू-

कांग्रेस ने ट्रंप-मस्क की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेल खाती रही है – जिनमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा, कोयला और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2015 से ही भारतीय मीडिया ने इस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया था: जहाँ भी मोदी विदेश दौरे पर जाते, उसके तुरंत बाद ही अडानी भी वहाँ एक्टिव हो जाते।

2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके तुरंत बाद अडानी समूह के कारोबार में तीव्र विस्तार हुआ। इस अवधि में समूह ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर और ऊर्जा उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की

2014 में अडानी की अनुमानित संपत्ति लगभग 3.5 अरब डॉलर थी और 2022 तक, ये थोड़े समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति तक बन गए थे। उस समय मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा था।

रिपोटर्स के अनुसार, 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान, मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए कथित रूप से अडानी के प्राइवेट जैट का इस्तेमाल किया था।

इसके अलावा, अडानी समूह ने रणनीतिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों, जैसे छह प्रमुख हवाई अड्डों (जिसमें मुंबई भी शामिल है) और प्रमुख

फण्ड्स) की निगरानी करें। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद विभिन्न आर्थिक और वित्तीय घटनाओं के कारण विभिन्न देशों के बीच फंड का प्रवाह बढ़ने लगा। इसका एक प्रमुख कारण था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटकर बाजार आधारित एक्सचेंज रेट की ओर जाना। इससे देशों की मौद्रिक नीतियों को नई दिशा में ढालना आवश्यक हो गया?

ये बदलाव उस नए वैश्विक आर्थिक माहौल का सीधा नतीजा थे, जो उस समय उभर रहा था। पहले यह माना जाता था कि किसी भी देश के कर्ंट अकाउंट (चालू खाते) में शुल्क बैलेंस होना चाहिए और किसी भी स्थिति में चालू खाता घाटा (स्ट्रक्चरल कर्ंट एकाउंट डेफिसिट) स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में यह सोच बदलने लगा। इस नए सिस्टम का मुख्य आधार उदाहरण यह था कि कुछ देशों (जैसे चीन) के पास भारी मात्रा में सरलस पूँजी जमा होने लगी और कुछ देशों (जैसे अमेरिका) पर भारी घाटा हो गया।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टॉक विधायक सचिन पायलट ने टॉक दौरे के दूसरे दिन करीब 10 गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की।

है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है।

पायलट ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार नहीं, 11 बार यह कहा कि व्यापार का लालच देकर सीज फायर करवाया है। यह बड़े दुख की बात

है कि अभी तक भी सर्वोच्च पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने इसका खंडन नहीं किया है, वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले। पायलट ने कहा कि जवाबी कार्यवाही तो उसे कहें हैं, जब इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के 95 हजार सैनिकों ने हथियार डाल दिये थे। पाकिस्तान में टूटी-फूटी सरकार है।

पीलपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत और गुर्जर आरक्षण को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि संविधान में जो राहत लोगों को दी गई है, उस पर अमल नहीं होगा तो जनता को उसका जवाब मांगने का अधिकार है। जो एग्रीमेंट है, गजट नोटिफिकेशन है, उनकी पालना नहीं होती है, यह तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए।

पायलट के दौरे के दौरान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, भंवर लाल बंशीवाल सहित, सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे।

क्या “इमरजेंसी” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया है। इसके विपरीत, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित 16 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि ऑपरेशन ‘सिंदूर’ और उससे जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने न तो इमरजेंसी सत्र को लेकर कांग्रेस के दावे पर कोई प्रतिक्रिया दी है, न ही इंडिया ब्लॉक के विशेष सत्र के अनुरोध पर कोई जवाब दिया है। ऐसे में स्थिति अभी भी गतिशील बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक सरकार की ओर से किसी अधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि विशेष संसद सत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।

3 अगस्त को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की बजाय एक ही पाली में आयोजित करके का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर एनबीई परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए गुहार लगा सकती है।

शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद एनबीई ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ ने समेत सुरक्षा संबंधी अन्य उपाय करने के बगैर अदालत को तीन अगस्त को आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

इसका डेटाबेस और रिसर्च संसाधन आर्थिक संकट के समय नीति बनाने में मददगार बन सकते हैं।

इस तरह, बी.आई.एस. अब अपनी मूल भूमिका से बहुत आगे निकल गया है और अब यह एक ऐसा स्थायी मंच बन गया है जहाँ दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के नीति निर्माता मिलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशन पर चर्चा करते हैं, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रह सके।

बी.आई.एस. (बैंक फॉर इंटरनैशनल सैटलमेंट) की स्थापना आज की आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक जैसी ब्रैट संस्थाओं से भी पहले हुई थी। यह अब ग्लोबल फायनैस में 100 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है।

बी.आई.एस. के पास वित्तीय संकटों का संस्थागत अनुभव, आर्काइव्स और निपटारे की पारम्परिक भूमिका अब कमजोर व अप्रासंगिक हो गयी।

लेकिन बी.आई.एस. के लिए एक नई भूमिका साफ दिखने दे रही थी,